हांगकांग संकट

drishtiias.com/hindi/printpdf/hong-kong-crisis

इस Editorial में ‘The Hindu’, ‘The Indian Express’, ‘Business Line’ में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस आलेख में हांगकांग संकट तथा इसके संदर्भ में चीन की नीति एवं भारत के पक्ष की चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

चीन को फिर एक बार विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। हांगकांग में पिछले दो माह से बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध का प्रमुख कारण हांगकांग के प्रत्यर्पण कानून में लाए जा रहे बदलाव हैं। हांगकांग एक स्वायत्त क्षेत्र है तथा इसकी शासन व्यवस्था चीन से भिन्न है। हांगकांग के लोगों का मानना है कि इस प्रकार के बदलाव हांगकांग की स्वायत्तता एवं ‘एक देश दो व्यवस्था’ के सिद्धांत को खतरे में डाल सकते हैं।

हांगकांग संकट का कारण

यह विवाद प्रत्यर्पण कानून में लाए गए बदलाव को लेकर उत्पन्न हुआ। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से हांगकांग से लोगों का प्रत्यर्पण चीन को किया जा सकेगा। हांगकांग विश्व में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है तथा विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक हित हांगकांग से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था व्यवसाय से संबंधित विवाद में दोषी पाए जाते हैं तो इनका प्रत्यर्पण चीन में किया जा सकता है। जबकि अभी तक हांगकांग ब्रिटिशकालीन कॉमन लॉ सिस्टम से काम कर रहा है और उसकी 1997 से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर के साथ ही प्रत्यर्पण संधि थी। इस प्रत्यर्पण विधेयक से हांगकांग के लोगों में यह भय पनपने लगा है कि चीन इस कानून के ज़रिये किसी भी ऐसे लोगों को, जो हांगकांग के राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हैं, नियंत्रित कर लेगा। इससे हांगकांग वासियों के राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएँगे।

हांगकांग की पृष्ठभूमि

हांगकांग लगभग एक शताब्दी तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था जिसे एक लंबी वार्ता के द्वारा वर्ष 1997 में चीन को सौंप दिया गया। इसके साथ ही एक देश दो व्यवस्था (One Nation Two System) की अवधारणा भी सामने आई। इस व्यवस्था के अनुसार हांगकांग को विशेष दर्जा दिया गया अर्थात् हांगकांग की शासन व्यवस्था चीन के मुख्य क्षेत्र से अलग होनी थी। चीन को रक्षा एवं विदेश संबंधी मामलों में अधिकार दिया गया जबकि अन्य मामले हांगकांग को दिये गए तथा यह तय किया गया कि वर्ष 2047 में अर्थात् चीन को हांगकांग सौंपे जाने के 50 वर्ष पश्चात् इस व्यवस्था को पुनरीक्षित किया जाएगा।

चीन एकदलीय व्यवस्था वाला देश है जिसमें हाल ही में एक बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार चीन का राष्ट्रपति जीवनपर्यंत इस पद पर रहेगा। जबकि हांगकांग का पिछली एक शताब्दी का इतिहास चीन से पृथक रहा है। ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण हांगकांग में लोकतांत्रिक विचारों का आगमन हुआ तथा हांगकांग की संस्कृति एवं पश्चिमी संस्कृति ने मिलकर कुछ नए विचारों को जन्म दिया, जो चीन से बहुत अलग हैं। हांगकांग पर चीन के आधिपत्य के अभी 20 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं और चीन एक देश दो व्यवस्था के विचार को मिटा देना चाहता है। यद्यपि चीन के मुकाबले अब हांगकांग का आर्थिक महत्त्व सीमित हो गया है लेकिन 1997 में हांगकांग जैसे छोटे से प्रांत की GDP चीन की GDP की 27 प्रतिशत थी जो अब घटकर 3 प्रतिशत के करीब ही रह गई है। चीन के मौजूदा राष्ट्रपति का विस्तारवादी रवैया 'एक देश दो व्यवस्था' को नकार रहा है तथा हांगकांग के चीन में पूर्ण विलय के लिये किसी भी सीमा तक जाने के लिये तैयार है।

अंब्रेला मूवमेंट

हांगकांग पर चीन के नियंत्रण के बाद से अब तक कई बार चीन को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर विरोध हुआ परिणामस्वरूप यह कानून वापस ले लिया गया। वर्ष 2014 में भी हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध को 'अंब्रेला मूवमेंट' की संज्ञा दी जाती है। हांगकांग की जनता को यह भरोसा दिलाया गया था कि वर्ष 2017 से हांगकांग के नागरिक अपने मुख्य कार्यकारी का निर्वाचन स्वयं कर सकेंगे किंतु चीन ने सिर्फ उन्हीं लोगों को इस पद के लिये चुनाव लड़ने की अनुमति दी जिन्हें चीन की साम्यवादी पार्टी का समर्थन हासिल हो। इससे हांगकांग के लोगों को अत्यधिक निराशा हुई। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों ने 2 महीने से भी अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिये लोगों ने छाते ('अंब्रेला) का उपयोग किया इसी कारण इसको 'अंब्रेला मूवमेंट' के नाम से पुकारा जाता है।

प्रदर्शनकारियों की मांग

प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध के पश्चात् इस विधेयक को निलंबित कर दिया गया था लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस विधेयक को पूर्णतः समाप्त घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त हांगकांग की मौजूदा मुख्य कार्यकारी कैरी लैम की बर्खास्तगी तथा उन सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की जा रही है जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

उपर्युक्त मांगों के अतिरिक्त हांगकांग के लोग चीन के प्रति सशंकित दृष्टिकोण रखते हैं तथा ऐसा मानते हैं कि चीन विभिन्न

माध्यमों के ज़रिये हांगकांग की विशेष स्थिति को समाप्त करना चाहता है। हांगकांग के लोग लंबे समय तक ब्रिटेन के उपनिवेश होने के कारण लोकतांत्रिक विचारों तथा पश्चिमी सभ्यता के करीब रहे हैं, साथ ही ये स्वयं भी अपनी संस्कृति तथा विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि चीन धीरे-धीरे अपने प्रभाव के ज़रिये हांगकांग की विशिष्ट पहचान को समाप्त करना चाहता है इसलिये लोग विरोध प्रदर्शन द्वारा चीन की हठधर्मिता के विरोध में उतर आते हैं।

चीन की स्थिति

मौजूदा समय में चीन आर्थिक मोर्चे पर गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर शुल्क में वृद्धि कर दी है। ध्यान देने योग्य है कि चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात पर निर्भर करती है परिणामतः चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 27 वर्षों के न्यूनतम वृद्धि दर पर पहुँच चुकी है। आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शन ने भी चीन के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है। इस विरोध प्रदर्शन को विभिन्न पश्चिमी देशों, यथा- अमेरिका, ब्रिटेन आदि तथा जापान का भी समर्थन प्राप्त है। चीन ने भी प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि यदि विरोध प्रदर्शन को नहीं रोका गया तो वह सैनिक कार्रवाई को भी अपने विकल्पों में शामिल कर सकता है। चीन के ऊपर वर्ष 1989 के **थ्यानमन आंदोलन** के नृशंस दमन का कलंक है जिसको लेकर विश्व में चीन की आलोचना होती रही है लेकिन 1989 की घटना चीन की सैनिक कार्रवाई की चेतावनी को मजबूत आधार प्रदान करती है, साथ ही हांगकांग के लोगों के मन में भय भी उत्पन्न करती हैं। यह भय हांगकांग में तेज़ी से बढ़ रही सैन्य बलों की संख्या से और भी तीव्र हुआ है। हालाँकि चीन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव है तथा उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हुई है, ऐसे में सैनिक कार्रवाई चीन के लिये अन्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

हांगकांग में पहले भी कई विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन वर्ष 2003, 2009, 2014 में हुए हैं। कुछ भू-सामरिक विश्लेषक इन प्रदर्शनों को विरोधों की पंच वर्षीय योजना की संज्ञा भी देते हैं। अतः चीन के लिये ये विरोध प्रदर्शन नए नहीं हैं, साथ ही विरोध की अवधि जितनी अधिक होगी, हांगकांग का आर्थिक नुकसान भी उतना ही अधिक होगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि हांगकांग के शेयर बाज़ार को पिछले दो माह में 500 बिलियन डॉलर की हानि हुई है। ऐसे में हांगकांग के विरोध प्रदर्शन लंबी अवधि तक नहीं चल सकते क्योंकि इनका आर्थिक मूल्य अत्यधिक है।

थ्यानमन आंदोलन एवं दमन

अप्रैल 1989 में 10 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी राजनीतिक आज़ादी की मांग को लेकर थ्यानमन चौक पर इकट्ठा हुए थे। चीन के वामपंथी शासन के इतिहास में इसे सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन कहा जाता है जो डेढ़ महीने तक चला। यह प्रदर्शन कई शहरों और विश्वविद्यालयों तक फैल गया था। प्रदर्शनकारी तानाशाही समाप्त करने और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बढ़ती महँगाई, कम वेतन आदि को लेकर भी लोगों में रोष व्याप्त था। 30 वर्ष पहले चीन में आर्थिक बदलाव के बाद राजनीतिक बदलाव की मांग को लेकर वर्ष 1989 में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। चीन में लोकतंत्र समर्थक छात्रों के नेतृत्व में किये गए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र थ्यानमन चौक ही था। छात्रों के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में चीन के लगभग 400 शहरों-कस्बों के लोग शामिल हुए थे, जो कम्युनिस्ट नेताओं से इस्तीफा चाहते थे। साथ ही देश में लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक समानता, प्रेस और बोलने की आज़ादी दिलाना भी इस प्रदर्शन के उद्देश्यों में शामिल था। इस दौरान अनगिनत प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी तथा 10 हज़ार को गिरफ्तार भी किया गया था।

भारत तथा चीन

भारत का रुख चीन की हांगकांग नीति के लिये उदासीन रहा है। भारत ने कभी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं किया है जबकि अन्य देश खुलकर हांगकांग के लोगों का समर्थन करते रहे हैं। चीन के साथ भारत पहले से उपस्थित मतभेदों को बढ़ाना नहीं चाहता है किंतु चीन का रुख कश्मीर जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी ही रहा है तथा वह हमेशा पाकिस्तान के समर्थन

में खड़ा रहा है। एक ओर चीन कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है वहीं स्वयं उईगर तथा हांगकांग के मामले में अमानवीय रुख अख्तियार करता है। भारत को भी चीन के रुख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिये। यदि चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो भारत को भी हांगकांग का खुलकर समर्थन करना चाहिये।

निष्कर्ष

हांगकांग संकट सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। भारत के हित भी हांगकांग में निहित हैं। भारत का डायस्पोरा हांगकांग में आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हांगकांग संकट में वृद्धि होती है अथवा चीन प्रदर्शनकारियों का बलपूर्वक दमन करता है तो भारत के हितों को भी क्षति पहुँच सकती है। इसके अतिरिक्त हांगकांग मुद्दा भारत के लिये चीन से कश्मीर मुद्दे को संतुलित करने का भी एक ज़रिया बन सकता है।

प्रश्न: हांगकांग के चीन को सौंपे जाने से अब तक कई बार हांगकांग को कई विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। हांगकांग में होने वाले विरोध प्रदर्शनों का क्या कारण है, साथ ही हांगकांग संकट के संदर्भ में चीन की नीति का विश्लेषण कीजिये?